बरघाट नगर परिषद के कामकाज पर अविश्वास की मुहर

पार्षदों ने दिया आंदोलन का अल्टीमेटम, बस स्टैंड शिफ्टिंग पर फैसला ठंडे बस्ते में ! जिम्मेदारों पर उठे बड़े सवाल

बरघाट नवभारत। तहसील मुख्यालय बरघाट की नगर परिषद पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगाते हुए सात पार्षदों ने कलेक्टर सिवनी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर प्रशासनिक हलकों में भूचाल ला दिया है, डीजल- पेट्रोल व्यय में कथित अनियमितताओं से लेकर वार्ड 13 के भीषण जलसंकट, करोड़ों की लागत से बने नवीन बस स्टैंड के निष्प्रयोग और घटिया डामरीकरण तक—ज्ञापन ने नगर परिषद की कार्यशैली पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं, पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित में उच्च स्तर पर शिकायत और लोकतांत्रिक आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

3 वर्षों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग

ज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक नगर परिषद द्वारा उपयोग किए गए डीजल एवं पेट्रोल के संपूर्ण व्यय का रिकॉर्ड सार्व जनिक करने की मांग की गई है, पार्षदों का आरोप है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगे जाने के बावजूद लगभग छह माह बीत जाने पर भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, पार्षदों ने इसे पारदर्शिता के अभाव और संभावित वित्तीय अनिय मितता का संकेत बताते हुए उच्च स्तरीय ऑडिट और दोषियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।

वार्ड 13 में पानी को लेकर हाहाकार

ज्ञापन के अनुसार वार्ड क्रमांक 13 में वर्षों से पेयजल का प्रमुख स्रोत रहा नलकूप बंद पड़ा है, परिणाम स्वरूप क्षेत्र में गंभीर जलसंकट खड़ा हो गया है,स्थानीय महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को दूर-दराज तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ स्थिति विकट होती जा रही है, पार्षदों ने तत्काल नलकूप चालू कराने या वैकल्पिक स्थायी जल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

बरघाट में यातायात सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लगभग 3 एकड़ क्षेत्र में निर्मित नवीन बस स्टैंड का उद्घाटन नवंबर 2019 में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन के कर-कमलों से हुआ था, इसके बावजूद आज तक बसों और टैक्सियों का संचालन पुराने, संकीर्ण बस स्टैंड से हो रहा है, इससे सिवनी-बालाघाट मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, 15 दिसंबर 2025 को राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक में बसों को नए स्टैंड में शिफ्ट करने का निर्णय हुआ था, परंतु आरोप है कि आज तक अमल नहीं हुआ। पार्षदों ने तत्काल संचालन प्रारंभ कराने की मांग की है।

डामरीकरण में 'तकनीकी खेल'

ज्ञापन का सबसे गंभीर हिस्सा नगर के विभिन्न वार्डों में हुए डामरीकरण कार्यों से जुड़ा है। निरीक्षण में निम्न अनियमितताएं बताई गईं, डामर की मात्रा अत्यंत कम, जिससे सतह शीघ्र उखड़ने लगी, सड़क की मोटाई निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं, बेस लेयर और सब-बेस की गुणवत्ता संदिग्ध, गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी पर्यवेक्षण का अभाव, पार्षदों का दावा है कि इन सड़कों की आयु सामान्य मानकों की तुलना में लगभग एक-चौथाई रह सकती है, जिससे शासकीय धन का दुरुपयोग और संभावित भ्रष्टाचार की आशंका प्रबल होती है, उन्होंने लोकनिर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री की अध्यक्षता में तकनीकी जांच समिति गठित कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कान्हीवाड़ा चौक पर शासकीय भूमि के अतिक्रमण को हटाकर यातायात सुचारु करने की मांग की गई है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि कुछ वार्डों में विकास कार्यों के मामले में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, सभी वार्डों में सड़क, पक्की नाली, जलापूर्ति और प्रकाश व्यवस्था समान रूप से प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन पर पार्षद श्रीमती संगीता रंजीत वासनिक (वार्ड 10), श्रीमती किरण नीरज सूर्यवंशी (वार्ड 13), रूचिका राकेश वासनिक (वार्ड 3), सुधा रामसिंह कंगाली (वार्ड 1), साक्षी ढालसिंह बिसेन (वार्ड 11), बाबर खान (वार्ड 2) और जितेंद्र उर्फ पप्पू सिंगारे (वार्ड 5) के हस्ताक्षर हैं, पार्षदों ने स्पष्ट कहा है कि यदि बिंदुवार कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ नहीं हुई तो वे उच्च स्तर पर शिकायत और लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

अब निगाहें कलेक्टर कार्यालय पर

बरघाट की सियासत में यह ज्ञापन नई बहस और संभावित जांच की दस्तक बन चुका है, जनता की निगाहें अब जिला प्रशासन पर टिकी हैं,क्या वित्तीय अभिलेख सार्वजनिक होंगे? क्या वार्ड 13 को पानी मिलेगा? क्या बसें नए स्टैंड से चलेंगी? और क्या सड़कों की गुणवत्ता की सच्चाई सामने आएगी? बरघाट की सड़कों, पानी और पारदर्शिता का यह सवाल अब सीधे प्रशासन की चौखट पर है, जवाब का इंतजार पूरे नगर को है।

मुफ्त का सरकारी राशन गल्ला दुकानों में !

अपात्र भी ले रहे मुफ्त का राशन, पात्रों को किया जा रहा परेशान

धारना कला नवभारत। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार राशन कार्ड धारक को 2028 तक मुफ्त सरकारी राशन गेहू और चावल प्रदान कर रही है किन्तु गरीब राशन कार्ड धारक ही सीधे राशन दुकान से मुफ्त का राशन लेकर गल्ला दुकानो मे बेचते नजर आ रहा है जिससे यह भी स्पष्ट हो गया है सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना का लाभ अपात्र तथा अमीर भी ले रहे है और यह किसी एक राशन दुकान की स्थिति नही है अपितु पूरे सिवनी जिले की है जहा पर इस योजना से भारी संख्या मे अमीर तथा अपात्र जुडकर सीधे लाभ ले रहे है और यही अनाज सीधे बाजार की गल्ला मे बिक रहा है।

अपात्र तथा अमीर भी ले रहे लाभ

वैसे इस जन कल्याण योजना के तहत कागज़ो मे दर्शित नियमो के अनुसार अनेको बिन्दू तथा नियम है जिनके आधार पर प्रधान मंत्री जन कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त का राशन प्राप्त किया जा सकता है किन्तु जमीनी हकीकत तो यह है की जिनकी लाखो रूपये माह की वार्षिक आय चार पहिया वाहन ट्रेक्टर एयर कंडीशनर परिवार मे सरकारी नौकरी प्लाट तथा जमीन जिनके पास उपलब्ध है ऐसे लोग भी मुफ्त का राशन लेते नजर आ रहे है ऐसी स्थिति मे सरकार से मिलने वाला मुफ्त का अनाज बाजार अथवा गल्ला दुकानो मे नही बिकेगा तो क्या ऐसे अमीर तथा अपात्र मोटे अनाज का सेवन करेगे अन्दाजा अपने आप लगाया जा सकता है जबकि वास्तविक गरीब आज भी राशन दुकान से मिलने वाला मुफ्त का राशन अपने घर ले जाकर उपयोग कर रहा है वही दूसरी तरफ मुफ्त का अनाज लेने वाले अपात्र तथा अमीरो का राशन गल्ला दुकान पहुच रहा है जो एक गंभीर समस्या है हालाकि सरकार द्वारा अपात्र लोगो की पहचान कर उनके कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया तेज तो कर दी है और 2025 26 मे प्रदेश के फर्जी लाभार्थी के नाम भी इस योजना से हटाये गये है और यही कारण है पिछली कार्रवाई मे विभाग द्वारा आयकर दाता जो मुफ्त का राशन का लाभ ले रहे थे ऐसे आयकर दाता ओ के नाम काटने की प्रक्रिया सामने आई है किन्तु वर्तमान मे भी ऐसे अपात्र तथा अमीरो के नाम इस योजना मे जुडे है जो टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर वाहन मे राशन लेने राशन दुकान पहुचते है ।

देर रात बज रहे डीजे साउंड पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही

सिवनी नवभारत। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के द्वारा अवैध रुप से डी.जे. साउंड प्रयोग कर शोरगुल करने वाले डीजे संचालकों के विरूध्द त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए है, जो एएसपी दीपक मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सचिन परते के मार्गदर्शन में नियम का उल्लंघन करने वाले डी.जे. संचालकों के विरूध्द लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली सिवनी द्वारा वर्तमान में आयोजित बोर्ड परीक्षाओं, छात्र-छात्राओं एवं स्थानीय रहवासियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए लॉन संचालकों के द्वारा बिना अनुमति निर्धारित समयावधि उपरांत भी तेज आवाज में शहर में डी.जे. बजाने, नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक पर कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 25/04/2026 को राशी लॉन के सामने सिवनी में बिना अनुमति संचालित किये जाने पर 01 डी.जे. साउंड सिस्टम के संचालक आयुष डेहरिया पिता सुनील डेहरिया पर धारा 7/15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए डी.जे. साउंड सिस्टम मय वाहन के जप्त करते हुए अपराध पंजीबध्द किया गया है। इससे पूर्व भी कोतवाली सिवनी पुलिस द्वारा बिना अनुमति तेज आवाज में संचालकों द्वारा डी.जे. साउंड सिस्टम बजाते पाये जाने पर पृथक पृथक अपराध पंजीबध्द किया गया था।

ग्राम छींदा में हुई महाराज निर्विकल्प स्वरुप की पादुका पूजन..!

छींदा नवभारत। ग्राम बंदेली (केवलारी) की श्रीराम कथा समाप्त होने के बाद ग्राम छींदा के शिव भक्तों के आमंत्रण पर महाराज निर्विकल्प स्वरुप अल्प समय के लिए ग्राम छींदा के पिंडी वाले शिव मंदिर परिसर में रुके। हाल ही में अपने निर्धारित तय कार्यक्रम के अनुसार ब्रम्हचारी निर्विकल्प स्वरुप सड़क मार्ग से अपने आश्रम झोतेश्वर जा रहे थे तभी ग्राम छींदा के शिव भक्तो के निवेदन पर रुके। प्रख्यात कथा वाचक - ब्रम्हचारी निर्विकल्प स्वरुप ने ग्राम छींदा के सिद्दी प्राप्त पिंडी वाले शिव मंदिर में स्थापित भगवान भोलेनाथ की पूजा - अर्चना की। यहां पुलिस चौकी छींदा के प्रभारी प्रमोद भारद्वाज ने महाराज निर्विकल्प स्वरुप की पादुका पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पुलिस चौकी छींदा स्टाफ के राजा बाबू शर्मा, प्रखर सिरोहिया, अमित रघुवंशी, गुलाब सिंह कुमरे और ग्राम छींदा के पंडित प्रेम मिश्रा, प्रदीप राय, अजय झारिया, राजकुमार यादव उप सरपंच, सुनील झारिया कमलेश राय, तुका झारिया, डा. हरलाल साहू सहित अनेक शिव भक्तों ने महाराज श्री निर्विकल्प स्वरुप जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया।

डोकररांजी आगजनी पीड़ित को रेड क्रॉस से मिली आर्थिक सहायता

कान्हीवाड़ा नवभारत। विकासखंड सिवनी के ग्राम डोकररांजी में विगत 22 अप्रैल को हुई भीषण आगजनी की घटना से प्रभावित परिवार को राहत प्रदान करने हेतु मानवीय पहल सामने आई है। रेड क्रास सोसायटी मध्यप्रदेश के अध्यक्ष पूर्व आईए एस अधिकारी डॉ .श्याम सिंह कुमरे एवं जिला कलेक्टर नेहा मीना के सहयोग से रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। उल्लेखनीय है कि अचानक लगी आग में संतलाल कनौजिया, राजकुमार राय, रामकुमार डेहरिया, नरेश यादव, प्रेमचंद गायकवाड एवं अरविंद बघेल सहित 6 परिवार के कच्चे मकान तथा पशु बांधने के सार पूरी तरह जलकर राख हो गए थे। इस दुखद घटना में एक गाय की जलकर मृत्यु हो गई, जबकि दो अन्य पशु घायल हो गए।

खूनी सड़क में दर्दनाक हादसा : बाइक सवार पर पलटा ट्रक

पति-पत्नि की दर्दनाक मौत

धारनाकला नवभारत। सिवनी बालाघाट रोड मे आज उस समय लोगो की आह निकल पडी जब चलती बाईक पर चावल से भरा ट्रक पलट गया जिसमे जनमखारी ग्राम के रहने वाले दीपचंद चौहान तथा पत्नि दुर्गा की मौके पर ही मौत हो गई

उल्लेखनीय है की दोनो पति पत्नि बरघाट से शादी समारोह से वापस अपने ग्रह ग्राम जनमखारी जा रहे थे लगभग 3 बजे जेवनारा और पौनार के बीच हिररी नदी के समीप चलती मोटर सायकल जिसमे दोनो पति पत्नि सवार थे के उपर चावल खंडा से भरा ट्रक पलट गया जिससे दोनो पति पत्नि की मौत हो गई लोगो ने तथा पुलिस प्रशासन ने चावल की बोरिया अलग कर ट्रक के नीचे दबी पति पत्नि को बाहर निकाला दुर्घटना इतनी भीषण थी मृतक के पैर ट्रक के पलटने से कट चुके थे तथा मोटर सायकल पूरी तरह चूरे मे तब्दील हो चुकी थी ।

मुख्यमन्त्री की घोषणा को बीत रहे दो वर्ष

यहा यह भी उल्लेखनीय है की नेताओ की घोषणा तो छोडो स्वयं प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के द्वारा रक्षा बंधन के पर्व मे बहनो से राखी तो बधवाई ही साथ सिवनी बालाघाट रोड को फोर लाईन मे तब्दील करने की घोषणा भी किन्तु लगभग दो वर्ष का समय बीतने के बाद भी मुख्य मन्त्री जी घोषणा पर अमल नही हो सका तो अन्दाजा लगाया जा सकता है अन्य घोषणाओ की जमीनी हकीकत क्या होगी आए दिन सिवनी बालाघाट रोड के आवागमन मे बढते दबाव रोड की बदहाल स्थिति के कारण दुरघटनाऐ घटित हो रही है और लोग बे समय ही काल के गाल मे समा रहे है और न जाने खूनी सडक के नाम से प्रसिद्ध यह सिवनी बालाघाट सडक और कितनी जाने लेती है ।

कब थमेगा भीषण दुर्घटनाओ का क्रम

उल्लेखनीय है की सिवनी बालाघाट रोड मे भीषण दुरघटना मे यह पहली मौत नही है आकडो पर गौर करे सैकड़ो परिवार सिवनी बालाघाट रोड की दुर्दशा के कारण खून के आसू रो रहे है किसी के परिवार की मुखिया की मौत तो किसी परिवार का चिराग इस बदहाल रोड की भेट चढ चुके है इसके साथ इस रोड के निर्माण को लेकर अनेको बार सत्याग्रह तथा आंदोलन भी हुऐ है तथा लोगो ने सिवनी बालाघाट रोड निर्माण के लिये अपने अपने प्रतिष्ठान तक बंद करते हुऐ ज्ञापन सौपा है इसके बाद भी सिवनी बालाघाट रोड मे आवागमन का बढता दबाव आऐ दिन हो रही दुर्घटनाओ मे मौत को लेकर सरकार गंभीर नही है।

पराली जलाने पर प्रशासन नाकाम, आगजनी से पर्यावरण और जनजीवन पर संकट

केवलारी नवभारत। केवलारी विकासखंड में पराली (नरवाई) जलाने पर रोक लगाने में प्रशासन की विफलता अब खुलकर सामने आने लगी है। क्षेत्र के अनेक गांवों में किसानों द्वारा खुलेआम खेतों में नरवाई जलाई जा रही है, जिससे कई जगह आगजनी की बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। इन घटनाओं में फसलों के साथ-साथ आसपास की वनस्पति,पशु और कभी-कभी ग्रामीण संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की सक्रियता नदारद दिखाई दे रही है।

हालात यह हैं कि पूरे विकासखंड के अधिकांश खेतों में नरवाई जलाई जा चुकी है और प्रशासन केवल कागजी दावों तक सीमित रह गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा समय-समय पर सोशल मीडिया और अखबारों में विज्ञप्ति जारी कर कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सख्ती या प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

इसके अलावा, नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। जमीन में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे भविष्य में फसल उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ता है। लगातार ऐसा होने से भूमि की गुणवत्ता गिरती जाती है।

प्रशासनिक लापरवाही और जागरूकता की कमी

पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए न तो पर्याप्त अभियान चलाए गए और न ही उन्हें वैकल्पिक उपायों की जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराए गए। किसान मजबूरी में पुराने तरीके अपनाने को विवश हैं। प्रशासन द्वारा केवल औपचारिकता निभाते हुए चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस समस्या का समाधान केवल सख्ती से नहीं बल्कि जागरूकता और सहयोग से संभव है। प्रशासन को चाहिए कि किसानों को हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (स्स्म्स) जैसी मशीनों की जानकारी और सब्सिडी उपलब्ध कराए और ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर पराली न जलाने के फायदे समझाए जाएं। वैकल्पिक उपयोग जैसे पशु चारा, जैविक खाद (कम्पोस्ट) और बायोफ्यूल बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित हो सके। स्थानीय स्तर पर निगरानी टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था की जाए।

यदि समय रहते केवलारी प्रशासन ने इस गंभीर समस्या को नियंत्रित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में यह स्थिति और भयावह हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और किसानों के बीच समन्वय बनाना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल क्षेत्र में प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

नारी शक्ति पर हुए कार्यक्रम

सिवनी। कलेक्टर मार्गदर्शन में जिले में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से जिले की विभिन्न परियोजनाओं—लखनादौन, बरघाट, घंसौर, केवलारी, छपारा एवं सिवनी (ग्रामीण-02) में संगोष्ठी, व्याख्यान, पदयात्रा, हस्ताक्षर अभियान, गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

पेट्रोल की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी

उगली नवभारत। अमेरिका - ईरान युद्ध के बाद वार क्राइसिस से संपूर्ण भारत में एलपीजी और पेट्रोल डीजल फ्यूल की समस्या नियमित देखने को मिल रही थी, जिसके आधार पर ग्रामीण अंचलों में अभी भी लंबी कतार लगाकर दो पहिया व चौपाया वाहनों को डीजल विशेष तौर पर पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतार पेट्रोल पंपों में देखी जा रही... सिवनी जिले के अंतर्गत विधानसभा के केवलारी के उगली मुख्यालय मोहबर्रा में दो पेट्रोल पंपो का संचालन पिछले एक दशक से हो रहा है. जहां बीते दिन एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहा है।

वहीं दूसरे पेट्रोल पंप में मात्र100 ? दोपहिया व 500 का पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है, बड़े शहरों में यह समस्या बिल्कुल नहीं है, उगली उप तहसील के अंतर्गत कुल 32 ग्राम पंचायत और लगभग 70 छोटे बड़े गांव का बाहुल्य आबादी वाला क्षेत्र है, कुल मिलाकर इस क्षेत्र अंतर्गत केवल तीन ही पेट्रोल पंप जहां ग्रामीण क्षेत्र की उपभोग कर्ता वाहन मालिकों को पेट्रोल डीजल की समस्याओं से जूझते नियमित देखा जा रहा है, इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संवेदन शील कलेक्टर और जिला प्रशासन को इस क्षेत्र की ईंधन और एलपीजी संबंधित समस्याओं के ऊपर ध्यान आकर्षण करवाने का प्रयाश किया जा रहा है,क्योंकि गांव कस्बे में भी बड़ी बसाहट वाले क्षेत्रीय ग्रामीण जीवन व्यापन करते हैं,जिनके दैनिक जीवन में वाहनों का आवा जाही और वर्तमान में अभी शादी समारोह के कार्यक्रम भी चल रहे है, आधुनिकता की इस दौर में पेट्रोल गाडियों से ही लोग अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों में इस तरह लंबी कतारों से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है. इनका कहना है... पेट्रोल पंप संचालक गौरव बिसेन... हम बड़े ट्रैकों में जेसीबी में टोटल डीजल नहीं दे रहे हैं और छोटे वाहनों में पेट्रोल, डीजल दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचल के पेट्रोल पंपों में समस्याएं हैं,जिसके ऊपर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. और दूसरे पंपों के संचालकों से भी संपर्क किया गया तो एक जानकारी दिए की दो-दो,तीन-तीन दिन के वेटिंग अंतराल में लोड उपलब्ध कराया जा रहा है एडवांस में डीडी देने के बाद भी ईंधन की आपूर्ति नियमित नहीं हो रही है, हमारे पंपों में हर एक-दो दिन के बाद ड्राई कंडीशन उत्पन्न हो जाती है,जिससे हमारे साथ-साथ ग्राहकों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है, इस तरह बात करें पूरी उगली उप तहसील के अंतर्गत पां. छपारा क्षेत्र में रेचना ग्राम में गीता फ्यूल्स और मोहबर्रा ग्राम में दो पेट्रोल पंप से पूरे क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की सुविधा उपलब्ध होता है, दैनिक उपयोगकर्ता छोटे वाहन मालिकों से पूछा गया तो बोले हमें प्रतिदिन 1 से 2 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, अब इतने से कार्य के लिए हम सिवनी,बालाघाट थोड़ी जाएंगे, कृपया शासन प्रशासन को ग्रामीण अंचलों में स्थित पेट्रोल पंपों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है.

बदहाली — महिला पुलिस नदारद, एसडीओपी भी मातृत्व अवकाश पर, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कागजों में मजबूत, जमीन पर कमजोर : स्टाफ की कमी से बेहाल घंसौर थाना

घंसौर नवभारत। सिवनी जिले के घंसौर थाना की जमीनी हकीकत पुलिस व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने ला रही है। एक ओर पहले से ही स्टाफ की भारी कमी, ऊपर से महिला पुलिसकर्मियों का अभाव—अब हालात और चिंताजनक तब हो गए हैं जब एसडीओपी नम्रता सोंधीया मातृत्व अवकाश पर हैं। उनके अवकाश में लखनादौन के एसडीओपी अपूर्व भलावी को घंसौर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिससे क्षेत्रीय पुलिस व्यवस्था पर दबाव और बढ़ गया है।

घंसौर थाना में महिला पुलिसकर्मियों की कमी पहले से ही बड़ी समस्या बनी हुई थी। अब एसडीओपी स्तर पर भी स्थायी नेतृत्व के अभाव में संवेदनशील मामलों की निगरानी और प्रभावी कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़िताओं को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

डबल प्रभार में अपूर्व भलावी जमीनी निगरानी कमजोर

लखनादौन एसडीओपी अपूर्व भलावी को घंसौर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऐसे में एक ही अधिकारी के जिम्मे दो क्षेत्रों की कानून व्यवस्था आ गई है। इससे फील्ड विजिट, मॉनिटरिंग और त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर आमजन की सुरक्षा पर पड़ रहा है। एक-एक जवान पर कई जिम्मेदारियां, सिस्टम थका हुआ। थाना स्तर पर स्वीकृत पदों के मुकाबले काफी कम स्टाफ के सहारे काम चल रहा है। गश्त, जांच, कोर्ट पेशी और वीआईपी ड्यूटी के बीच पुलिसकर्मी लगातार दबाव में हैं। नतीजतन, कई मामलों में कार्रवाई में देरी और अपराध नियंत्रण में ढिलाई देखने को मिल रही है।

देरी से कार्रवाई, बढ़ता अपराध जिम्मेदार कौन?

लगातार मिल रही शिकायतों के अनुसार, कई मामलों में समय पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और आमजन में असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर इस बदहाल व्यवस्था के लिए जवाबदेह कौन है?

उच्च अधिकारियों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गंभीर समस्या को कई बार उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है?

जनता में आक्रोश, जल्द समाधान की मांग

क्षेत्रीय नागरिकों ने मांग की है कि घंसौर थाना में तत्काल पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की जाए, विशेषकर महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, एसडीओपी स्तर पर स्थायी और पूर्णकालिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई जा रही है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच अब सभी की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं। यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक चिंताजनक हो सकती है।